गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 254
दि. 14.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'गांधी के बाद पीएम मोदी सबसे बड़े लीडर', अमेरिका से आई प्रधानमंत्री मोदी के लिए तारीफ

(जीएनएस)।

पीएम मोदी के लिए अमेरिका से तारीफ आई है. अमेरिका में पीएम मोदी को गांधी के बाद सबसे बड़ा लीडर बताया गया है. वाशिंगटन में रिच मैककॉर्मिक और अमी बेरा ने पीएम मोदी के नेतृत्व, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और भारत-अमेरिका साझेदारी की मजबूती की सराहना की.

अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा, कहा, 'गांधी के बाद पीएम मोदी सबसे बड़े लीडर'

वाशिंगटनः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका से तारीफ आई है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की अमेरिका में भी खूब सराहना की जा रही है. प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा अहम नेता बताया है, जो वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को नई दिशा दे रहे हैं. उनका कहना है कि वाशिंगटन पीएम मोदी के नेतृत्व को भारत-अमेरिका साझेदारी की दीर्घकालिक मजबूती के लिए केंद्रीय मानकर चल रहा है. वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सोच की प्रशंसा की.

मैककॉर्मिक ने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण पूरी तरह से देशहित पर केंद्रित है और भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप है. वे अच्छे अर्थों में बेहद राष्ट्रवादी हैं. रिच मैककॉर्मिक (जो कांग्रेसनल इंडिया कॉकस के को-चेयर भी हैं) ने कहा, 'पीएम मोदी अपने देश का वैसे ही ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने देश का रखते हैं। वह भारत में उत्पादकता, विस्तार और नई तकनीकों को लाना चाहते हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सांसद पीएम मोदी की उस सोच को समझते हैं जिसमें वे रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में देश के भीतर क्षमता निर्माण पर जोर देते हैं. प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत की सैन्य ताकत देश के अंदर ही विकसित हो.

रिच मैककॉर्मिक ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं. भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदे जाने का जिक्र करते हुए मैककॉर्मिक ने कहा, 'हमें यह पसंद नहीं है, लेकिन वह अपने देश के हित में ऐसा कर रहे हैं ताकि सस्ती ऊर्जा के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार दे सकें.' हालांकि, मैककॉर्मिक ने यह भी कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ तालमेल की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं. आखिर में, वह जानते

हैं कि हम विचारधारा के स्तर पर समान सोच रखते हैं.'

मैककॉर्मिक ने यह भी कहा कि मेरे विचार से पीएम मोदी आधुनिक इतिहास के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं. वह शायद गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस विचार का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता को समझने की बात कही थी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह उस राजनेता पर भरोसा नहीं करते, जिसने कभी भारत को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक ट्रेन के सामान्य कोच में यात्रा न की हो.

कार्यक्रम में मौजूद अमेरिकी कांग्रेस के सबसे लंबे समय से सेवा दे रहे भारतीय-अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल भारत के वैश्विक उभार के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा, 'भारत हमारी पूरी इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है और यह रणनीतिक सोच कई अमेरिकी प्रशासन में लगातार बनी हुई है.' अमी बेरा ने कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार और बढ़ते आत्मविश्वास ने वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक समीकरणों को नए सिरे से आकार देना शुरू कर दिया है.

बिहार में बड़ा खेला! कांग्रेस के सभी 6 विधायक 'लापता', किस दल में होंगे शामिल?

(जीएनएस)। बिहार की राजनीति में एक बार फिर 'खेला' होने के संकेत मिल रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित 'दही-चूड़ा' भोज में पार्टी के सभी 6 विधायकों का नदारद रहना चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 'खरमास' खत्म होते ही बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और ये विधायक एनडीए का दामन थाम सकते हैं।

भाजपा और लोजपा (रामविलास) के नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसे महज अफवाह बता रहे हैं।

पटना में कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित पारंपरिक दही-चूड़ा भोज उस समय चर्चा में आ गया जब पार्टी

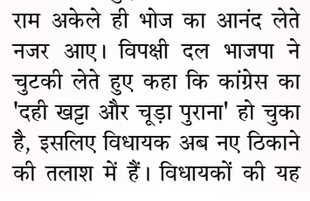

के निर्वाचित सभी 6 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अकेले ही भोज का आनंद लेते नजर आए। विपक्षी दल भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का 'दही खट्टा और चूड़ा पुराना' हो चुका है, इसलिए विधायक अब नए ठिकाने की तलाश में हैं। विधायकों की यह अनुपस्थिति पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और संभावित विद्रोह की ओर इशारा कर रही है।

खरमास के बाद 'ऑपरेशन लोटस' की चर्चा

बिहार की राजनीति में यह माना जाता है कि शुभ कार्यों की शुरूआत खरमास (14 जनवरी) के बाद होती है। लोजपा (आर) के नेता और मंत्री संजय सिंह ने खुला दावा किया है कि मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने भी कहा है कि केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि राजद (फखऊ) के भी कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं।

पीएम मोदी से मिले मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने चर्चा

नई दिल्ली। (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की।

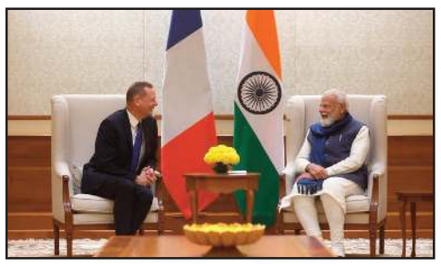

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार के मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने भारत-फ्रांस के बीच मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोन से मिलकर बेहद खुशी हुई। हमने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की, जो कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित है और मजबूत व भरोसेमंद है। उन्होंने कहा, हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि हमारा सहयोग नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, खासकर ऐसे समय में जब हम भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष मना रहे हैं।

विज्ञापन

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। हम राष्ट्रपति मैक्रों का जल्द ही भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

वहीं, नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास ने भी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फरवरी 2026 में होने वाली भारत यात्रा से पहले राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चर्चा में होराइजन 2047 रोडमैप के अनुरूप भारत की रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर फोकस किया गया।

भगवंत मान सरकार ने पनबस-पीआरटीसी के बड़े विस्तार के माध्यम से गांवों से शहरों तक परिवहन संपर्क को किया मजबूत

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हाल के वर्षों में सरकारी बस सेवाओं में किए गए व्यापक विस्तार के कारण पंजाब की परिवहन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा रहा है। सरकार के बेड़े में 1,279 बसें शामिल करने का निर्णय केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए किफायती, सुरक्षित, सुलभ और निर्बाध संपर्क को प्राथमिकता देने की दिशा में एक ठोस कदम है।

वर्तमान में पंजाब सरकार के अधीन 2,267 बसें संचालित की जा रही हैं, जिनमें से 1,119 पनबस (पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) के अधीन हैं। मान सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खरीद और लीज-दोनों माध्यमों से बसों के विस्तार को सूझ-बूझ के साथ मंजूरी दी गई है, जिससे वित्तीय बोझ की परवाह किए बिना विस्तार सुनिश्चित किया गया है। इस विस्तार के तहत 796 बसें सीधे खरीदी जाएंगी, जबकि 483 बसें किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, जिससे राज्य की मांग और रूट संबंधी जरूरतों का सुव्यवस्थित ढंग से समाधान किया जा सकेगा।

इस विस्तार योजना के अंतर्गत 696 साधारण बसों और 100 मिडी बसों की खरीद की जाएगी। पनबस को 387 साधारण बसें दी जाएंगी, जबकि पीआरटीसी (पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) को 309 साधारण बसें मिलेंगी। पीआरटीसी में 100 मिडी बसें शामिल की जाएंगी, क्योंकि ये छोटी बसें शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ग्रामीण रूटों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जहां बड़ी बसों का संचालन संभव नहीं होता। यह विस्तार छोटे कस्बों और गांवों की लंबे समय से चली आ रही परिवहन संबंधी मांग को पूरा करेगा, जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था।

यह कदम दर्शाता है कि भगवंत मान सरकार किस प्रकार जमीनी स्तर पर सुधारों को लागू कर रही है। सभी नई खरीदी गई साधारण बसें एआईएस-153 मानकों को पूरा करेंगी, जिससे सुरक्षा और सुलभता में वृद्धि होगी। आंशिक रूप से दिव्यांग यात्रियों के लिए बेहतर बोर्डिंग सुविधाएं, व्हीलचेयर-अनुकूल पहुंच, कम शोर और कंपन तथा बेहतर प्रदर्शन-यात्री और चालक दोनों के लिए अधिक आरामदायक और सम्मानजनक अनुभव सुनिश्चित करते हैं।

इन बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्पष्ट आपातकालीन संकेत, जीपीएस, सीसीटीवी, एलईडी लाइटें और नाइट लैंप जैसी सुविधाएं विशेष रूप से रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित करती हैं।

जब भारत दुनिया की सांस्कृतिक बहसों की अगुवाई करेगा

भारत की बढ़ती वैश्विक सांस्कृतिक भूमिका का एक मजबूत प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह फेस्टिवल सिर्फ किताबों और लेखकों का मंच नहीं, बल्कि विचारों, राजनीति, इतिहास और रचनात्मकता का ऐसा संगम है, जहां भारत की आवाज

दुनिया भर के विद्वानों और रचनाकारों के साथ गूंजेगी।

इस बार 25 से ज्यादा देशों से आने वाले प्रतिभागी जयपुर में एक साथ जुटेंगे, जिससे यह आयोजन सच मायनों में अंतरराष्ट्रीय संवाद का केंद्र बन जाएगा।

प्रगति मॉडल से उत्तर प्रदेश बना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजनः मुख्यमंत्री

'प्रगति' नए भारत की कार्यसंस्कृति का प्रतीक : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के समन्वय से सुनिश्चित हो रहे हैं ठोस परिणाम

इंटर-एजेंसी बाधाएँ समाप्त, अनुमतियों और मंजूरियों में आई तेजी

बॉटलनेक स्टेट से ब्रेकथ्रू स्टेट बना उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री

₹10.48 लाख करोड़ की 330 परियोजनाओं के साथ यूपी के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो

यूपी में 39% परियोजनाएँ पूरी, 202 परियोजनाएँ समयबद्ध प्रगति पर

₹2.37 लाख करोड़ की 128 परियोजनाएँ पूर्ण, ₹8.11 लाख करोड़ की 202 परियोजनाएँ प्रगति पर

लखनऊ, (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है। मंगलवार को आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रगति' उस प्रशासनिक मॉडल को दर्शाता है, जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी और 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति ने यह सिद्ध किया है कि जब इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती हैं, तो आउटकम अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूती देते हुए प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, जहां अंतर-मंत्रालयीय और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यही मॉडल आगे चलकर 'प्रगति' के राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में विकसित हुआ, जिसने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में टीम इंडिया अप्रोच को मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं, बल्कि गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसने शासन को फाइल-केंद्रित संस्कृति से फील्ड-आधारित परिणामों की दिशा में अग्रसर किया है। इसके माध्यम से निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत की बबार्दी रुकी है तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के साथ-साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

पाला पड़ने से फसलों पर खतरा, किसानों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है।

खासकर पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक इन क्षेत्रों में भीषण ठंड बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिया गया है।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर पंजाब और चंडीगढ़ से सटे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों, सूखी घास और वाहनों की खिड़कियों पर जमी बर्फ की परत साफ दिखाई दी।

'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेफ्ट को मिला भाजपा का साथ

केरल का नाम बदलकर केरलम करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में केंद्र सरकार के दखल देने का अनुरोध किया.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध करते हुए, इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने पत्र में जून 2024 में केरल विधानसभा की तरफ से जारी सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक नाम केरल बदलकर केरलम करने को लेकर पास किए बिल का भी जिक्र किया. साथ ही उन्होंने विधानसभा के फैसले को मानते हुए, एक पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को भी भेजी है.

बेंगलूरू में 6 घंटे बिजली सप्लाई रहेगी बाधित, बेस्काम ने जारी की प्रभावित एरिया की सूची

बेंगलुरु के कई इलाकों में बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु बिजली आपूर्ति कंपनी (BESCOM) ने बुधवार के लिए शहर के कई प्रमुख इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की है। आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण यह कटौती सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।

अवकाश की सूचना

14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर कार्यालय में अवकाश है इसलिए 15 जनवरी का समाचार पत्र नहीं मिलेगा। अगला समाचार पत्र 16 जनवरी 2026, शुक्रवार के दिन प्राप्त हो सकेगा

- सम्पादक

फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत - गुजरात यात्रा संपन्न

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी अड्डे से जर्मनी के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित महानुभावों ने जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज को भावपूर्ण विदाई दी।

भावपूर्ण विदाई

गांधीनगर, 13 जनवरी : फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत- गुजरात यात्रा मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

श्री मर्ज ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रणनीतिक कार्यक्रमों में तथा भारत-जर्मन सीईओ फोरम में सहभागिता करने के बाद मंगलवार को अहमदाबाद हवाई

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, शहर पुलिस आयुक्त श्री जी. एस. मलिक, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी, जिला कलेक्टर सुजीत कुमार, विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधिकारी सहित वरिष्ठ राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

सशक्त हो रही महिला की भूमिका

आज के भारत में औरतें एक मज़बूत धागे के तौर पर उभर रही हैं जो देश के सामाजिक ताने-बाने में रंग, ताकत और लचीलापन जोड़ती हैं। उनका आगे बढ़ना कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, बातचीत और ज्ञान और बराबरी की वकालत करने वाली इस्लामी शिक्षाओं की नई समझ का नतीजा है।

आज भारत-पाक सबकॉन्टिनेंट में औरतों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ज़्यादातर औरतों को अपने बेसिक फ़ैसले लेने का हक नहीं दिया जाता, उन्हें घर की काउंसिल में शामिल नहीं किया जाता, उनके मुकाबले लड़कों को हर तरह की आज़ादी दी जाती है, लड़कियों पर बेवजह की रोक-टोक और पाबंदियां लगाईं जाती हैं, उनकी समझदारी और ज्ञान को शक की नज़र से देखा जाता है, मौके और विरासत देते समय उन्हें नज़रअंदाज़ किया जाता है, उन्हें अपनी छोटीछोटी ज़रूरतों और अपनी ज़िंदगी के बेसिक और निजी फ़ैसलों के लिए भी घर के मर्दों पर निर्भर रहना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उनके सेल्फ -कॉन्फ़ि डेंस और फ़ैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ता है और ज़िंदगी भर उनके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है।

अगर हम इतिहास और मौजूदा हालात देखें तो किसी भी देश और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य और समाज की तरक्की में महिलाओं का अहम रोल रहा है।

एक पढ़ी-लिखी, मज़बूत, कॉन्फ़िडेंट और सम्मानित महिला हर तरह के हालात का डट कर मुकाबला कर सकती हे । अगर महिलाओं को समाज में मज़बूत बनाना है, तो माता-पिता को उन्हें बचपन से ही घर की सलाह में शामिल करना होगा। इससे न सिर्फ़ उनका कॉन्फ़िडेंस बढ़ेगा, बल्कि एक कॉन्फ़िडेंट महिला भविष्य में एक एम्पावर्ड महिला भी बनेगी।

उन्हें अपने पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़े पैसले लेने की ताकत देना बहुत ज़रूरी है। इससे महिलाओं को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कॉन्फ़िडेंस मिलेगा और उनमें ज़िंदगी के हर पहलू में बिना किसी रुकावट के, चाहे मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रुकावटें हों, सही पैसले लेने की हिम्मत आएगी।

मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की ताकत ने महिलाओं की तरक्की के लिए नए दरवाज़े खोले हैं, और वे समाज की गैर- ज़रूरी रुकावटों को तोड़कर और पुरानी सोच को पीछे छोड़कर इंसानी तरक्की के नए चैप्टर लिख रही हैं। असल में, एजुकेशन किसी को भी एम्पावर करने की कहानी का आधार है, और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह एक हक और ऊपरवाले का हुक्म दोनों है। आज के भारत में मुस्लिम औरतें एक मज़बूत धागे के तौर पर उभर रही हैं जो देश के सामाजिक ताने-बाने में रंग, ताकत और लचीलापन जोड़ती हैं। उनका आगे बढ़ना कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, बातचीत और ज्ञान और बराबरी की वकालत करने वाली इस्लामी शिक्षाओं की नई समझ का नतीजा है। आज, क्लासरूम से लेकर कोर्टरूम तक, हॉस्पिटल से लेकर बोर्डरूम तक, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उड़ने वाले हवाई जहाज़ तक, लड़ाई के मैदान से लेकर खेल के मैदान तक, यूनिवर्सिटी से लेकर मंत्रालयों तक, मुस्लिम महिलाएं रुकावटों को तोड़ रही हैं और ज़िंदगी की एक नई तस्वीर पेश कर रही हैं, कि भारतीय और मुस्लिम दोनों होने का क्या मतलब है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, मुस्लिम लड़कियों के लिए बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप स्कीम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी सरकारी पहलों ने तालीम तक पहुंच को और बढ़ाया है और हाल के सालों में, प्राइमरी और सेवेंडरी लेवल पर मुस्लिम लड़कियों का एनरोलमेंट तेज़ी से बढ़ा है। इस वजह से, कई मुस्लिम लड़कियां अब मेडिसिन, इंजीनियरिग, लॉ और मैनिटीज में हायर एजुकेशन ले रही हैं।

कई मुस्लिम लड़कियों ने सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में शानदार सफलता हासिल की है, जिससे मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट में एक और चैप्टर जुड़ गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब का शिलान्यास

- गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा राज्य सरकार संचालित देश का प्रथम 'बीएसएल-4' लैब
- गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरूआत : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

-: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह :-

- यह लैब जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच तथा जैव-सुविधाओं का सुदृढ़ किला सिद्ध होगा
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोधकताओं तथा युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोलेगा यह लैब
- पिछले एक दशक में देश की बायो-इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 166 बिलियन डॉलर के पार पहुँची
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज 'विज्ञान' तथा 'विरासत'; दोनों को साथ लेकर विकास कर रहा है

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- देश को संभावित महामारियों से सुरक्षित बनाने का 'बीएसएल-4 लैब प्रोजेक्ट' प्रधानमंत्री के हेल्थ केयर फॉर ऑल तथा अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विजन है
- बीएसएल-4 लैब में होने वाला अनुसंधान उपचार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में परिवर्तन लाने वाला ट्रांजिशनल रिसर्च बनेगा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की प्रेरक उपस्थिति

गांधीनगर, 13 जनवरी : केन्द्रीय

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के प्रथम अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब तथा 'एनिमल बायो-सेफ्टी लेवल' सुविधा का गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में शिलान्यास किया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया भी उपस्थित रहे।

इस समारोह के दौरान गुजरात बायो-टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' सुविधा को भारत सरकार की 'बायोई3 नीति' अंतर्गत 'नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च फैसिलिटी' के रूप में नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरूआत हुई है। पुणे के बाद देश का यह केवल दूसरा उच्च स्तरीय लैब है, लेकिन राज्य सरकार की विशेष पहल से 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह देश का पहला बीएसएल-4 लैब बनेगा। भविष्य में यह लैब जानलेवा वायरसों से लड़ने के लिए भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच तथा जैव-सुविधाओं का मजबूत किला सिद्ध होगा।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ होना चाहिए'; विजन को दोहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह लैब शोधकताओं तथा युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोलेगा। विशेषकर पशुओं से इंसानों मं फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'वन हेल्थ मिशन' को इस लैब से गति मिलेगी। हाल ही में गुजरात द्वारा झेले गए चांदीपुरा तथा लम्पी स्किन डिसीज जैसे संकटों के विरुद्ध इस प्रकार की रिसर्च आधारित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य थी।

तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच भारत बढ़ाएगा रक्षा बजट? क्या है सरकार का प्लान

(जीएनएस)।

दुनियाभर में गहराते युद्ध के बादलों और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत का आगामी रक्षा बजट अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका-वेनेजुएला तनाव और ताइवान पर चीन की बढ़ती नजरों ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को अस्थिर कर दिया है।

अमेरिका द्वारा अपने रक्षा बजट को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के प्रस्ताव ने अन्य देशों पर भी सैन्य तैयारी बढ़ाने का दबाव बनाया है। ऐसे में भारत के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गई है।

वैश्विक उथल-पुथल और अमेरिकी आक्रामकता

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला और ईरान के प्रति सख्त रुख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बना रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की हिरासत ने दुनिया को चौंका दिया है। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर चीन द्वारा ताइवान पर दबाव बढ़ाने की आशंका भी प्रबल हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि महाशक्तियों की यह बढ़ती सैन्य सक्रियता भारत जैसे देशों को अपने रक्षा संसाधनों और कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है।

चीन की चुनौती और एलएसी पर चौकसी

चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनाव बरकरार है। बीजिंग की रणनीतिक गणना में भारत-अमेरिका की बढ़ती निकटता और तिब्बत की स्थिति प्रमुख कारक हैं। चीन अचानक कोई कदम उठाने के बजाय एक सोची-समझी रणनीति के तहत भारत पर दबाव बनाता है। इसी सामरिक चुनौती का सामना करने के लिए भारत को अपनी

सीमा सुरक्षा बुनियादी ढांचे और निगरानी तंत्र को और अधिक पुख्ता करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बजट 2026 में विशेष प्रावधान अपेक्षित हैं।

बढ़ते खतरों को देखते हुए इस साल के केंद्रीय बजट में रक्षा आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा क्षेत्र को 6.8 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 1.8 लाख करोड़ रुपये केवल आधुनिकीकरण के लिए थे। इस बार सरकार का ध्यान केवल हथियारों की खरीद पर ही नहीं, बल्कि ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष युद्ध (स्पेस वॉरफेयर) जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी होगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी तैयारी को भविष्य के 'टेक्नोलॉजी-आधारित' युद्धों के अनुरूप ढाल रहा है।

आत्मनिर्भर भारत और पांच सूत्रीय रक्षा नीति

भारत की वर्तमान रक्षा नीति 'आत्मनिर्भरता' और 'मेक इन इंडिया' के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। इसके पांच मुख्य आधार हैं: चीन को दीर्घकालिक चुनौती मानना, दो मोर्चों (चीन-पाक) पर युद्ध की तैयारी, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा, हिंद महासागर में नौसेना का विस्तार और आधुनिक तकनीक का समावेश। सरकार का लक्ष्य वेतन और पेंशन के बोझ को प्रबंधित करते हुए पूंजीगत खर्च बढ़ाना है, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी अपनी पहचान बना सके।

राजकोट में होगी असली 'अग्निपरीक्षा', भारत के लिए अनलकी रहा है यह मैदान, क्या गिल तोड़ पाएंगे पनौती?

(जीएनएस)।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, लेकिन राजकोट के इस मैदान का इतिहास भारतीय टीम के लिए किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि यह मैदान मेजबान टीम के लिए अब तक बहुत ज्यादा लकी साबित नहीं हुआ है।

राजकोट में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब

राजकोट के इस स्टेडियम पर पहला वनडे साल 2013 में खेला गया था, जहां इंग्लैंड ने भारत को 9 रनों से हराकर चौंका दिया था। इसके बाद 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को यहां 18 रनों से धूल चटाई। भारत को अपनी पहली जीत के लिए साल 2020 तक इंतजार करना पड़ा, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। हालांकि, यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और 2023 में

ऑस्ट्रेलिया ने फिर से भारत को यहां 66 रनों से करारी शिकस्त दे दी।

4 वनडे में से तीन में मिली है हार

भारत ने इस मैदान पर अब तक 4 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और केवल 1 मैच में जीत मिली है। इस मैदान का एक दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू यह है कि यहां अब तक हुए सभी मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है। भारत ने भी अपनी इकलौती जीत (2020) तब दर्ज की थी जब उसने पहले बैटिंग की थी। इसका मतलब साफ है कि यहां बाद में बल्लेबाजी करना यानी रनों का पीछा करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म दमदार

अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक का स्कोर खड़ा कर देती है, तो उसे चेज करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल के लिए टॉस जीतना और पहले बल्लेबाजी का फैसला करना मैच की आधी स्क्रिप्ट लिखने जैसा होगा। भले ही रिकॉर्ड्स डराने वाले हों, लेकिन टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म राहत देने वाली है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज शानदार लय में हैं। वहीं, कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी रनों की बारिश कर रहा है। मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की मौजूदगी टीम को वह गहराई देती है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने या बड़ा स्कोर बनाने की ताकत रखती है।

पुस्तकें कराती हैं आत्मबोध और राष्ट्रबोध

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 की थीम 'भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा' केवल एक विषय नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत स्मृति और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त उद्घोष है। यह थीम हमारे सैन्य इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों को सामने लाती है, जहाँ रणभूमि में अदम्य साहस और निर्णयों में गहन बौद्धिक प्रज्ञा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में इस थीम को अत्यंत सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह विषय भारत की गौरवशाली परंपराओं, अपराजेय साहस और समृद्ध बौद्धिक विरासत को रेखांकित करता है। वास्तव में, भारतीय सैन्य इतिहास केवल युद्धों और विजय-पराजय की कथा नहीं है, बल्कि रणनीति, नैतिकता, नेतृत्व और कर्तव्यबोध की जीवंत पाठशाला रहा है।

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत की सैन्य परंपरा ने यह सिद्ध किया है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप विवेक से संचालित होता है। चाणक्य की अर्थनीति से लेकर शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति, और स्वतंत्र भारत की सेनाओं की आधुनिक युद्ध-कुशलता-हर चरण में 'शौर्य' के साथ 'प्रज्ञा' की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

पुस्तक मेला 2026 की यह थीम विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। यह उन्हें इतिहास से सीख लेने, राष्ट्रभक्ति को भावनात्मक नारे से आगे बढ़ाकर कर्तव्य और अनुशासन के रूप में समझने की दिशा देती है। साथ ही, यह संदेश भी देती है कि सशक्त राष्ट्र वही होता है, जो अपने अतीत को जानता, समझता और उससे भविष्य की दिशा तय करता है।

12 जनवरी, 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में चयनित 43 युवा लेखकों से किया। उन्हें सार्थक पुस्तकें लिखने के लिए मेंटरशिप अवधि का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जो देश के युवाओं को पढ़ने, लिखने और ज्ञान के साथ गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने शोध सामग्री तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया और निर्देश दिया कि राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (एनबीटी) के माध्यम से भौतिक और डिजिटल दोनों संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि लेखकों को 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ओएनओएस) पहल के तहत संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। उनके अकादमिक और शोध संबंधी सहयोग को पुख्ता करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि चयनित लेखकों को अपने-अपने क्षेत्रों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाए ताकि वे अपनी किताबों को तैयार कर सकें।

2026 में मोदी छोड़ेंगे पीएम पद? कौन होगा उत्तराधिकारी? चौंका रही है ये नई भविष्यवाणी

(जीएनएस)।

भारत की राजनीति में 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसकी वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि देश के जाने माने ज्योतिषियों की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। सवाल बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में अपना पद छोड़ेंगे या उनकी सत्ता और मजबूत होगी। इसी के साथ यह भी चर्चा है कि क्या इस साल उनका उत्तराधिकारी भी तय हो जाएगा।

क्या जाएगी पीएम मोदी की कुर्सी?

ज्योतिषी पवन सिन्हा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंगल की महादशा में हैं, जो अगस्त 2027 तक चलेगी। इस ग्रह योग का असर यह बताता है कि मोदी अपनी कुर्सी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके अनुसार मंगल में शुक्र का प्रभाव यह संकेत देता है कि मोदी फिलहाल भाजपा को मजबूत करने में जुटे रहेंगे और 2026 तक उनके पद पर बने रहने की संभावना ज्यादा है। अगर वो पीएम पद छोड़ते हैं या फिर कोई बदलाव होगा तो वह केवल निजी कारणों से ही हो सकता है, राजनीतिक मजबूरी से नहीं।

ज्योतिषी पवन सिन्हा अपनी भविष्यवाणी में कहते हैं,

"देखिए, जब तक मंगल में केतु का अंतर शुरू नहीं होता, मोदी जी की कुंडली में तब तक, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यानी तब तक मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे। भाजपा के पास मोदी जी जैसा एक चमकता हुआ चेहरा है। मोदी की बात देश के युवा, बुजुर्ग बच्चे यानी हर वर्ग मानता है। इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, एक ऐसी जनता है, लगभग 30-40% लोग, मोदी की बात मानते हैं। पीएम मोदी की बात को फॉलो करते हैं। इसलिए एक ऐसे चेहरा का होना चुनाव के वक्त जरूरी होता है। चूंकि मंगल की महादशा अभी चल रही है, और ये अगस्त 2027 तक चलेगी, यानी मंगल में शुक्र का असर रहेगा। यानी इस वक्त में मोदी जी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे अगर वो किसी निजी कारण से इस्तीफा देते हैं, तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल वो अपने पद पर बने रहेंगे। वो इस वक्त भाजपा को उठाने की कोशिश में रहेंगे।"

2026 में कुर्सी डगमगाएगी लेकिन...

ज्योतिषी वाई राखी की भविष्यवाणी और भी ज्यादा सनसनीखेज है। उनका कहना है कि 2026 में पीएम मोदी की कुर्सी जरूर हिलेगी, लेकिन वह हालात को संभाल लेंगे। इस दौरान गठबंधन सरकार में भी उथल-पुथल हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी अस्थिरता के संकेत बताए गए हैं। सियासी हलचल खासतौर पर दक्षिण भारत से उठ सकती है।

कौन होगा पीएम मोदी उत्तराधिकारी?

पवन सिन्हा का यह भी कहना है कि फरवरी 2025 के बाद, जब मंगल में शनि का प्रभाव शुरू हुआ, तभी से मोदी के मन में उत्तराधिकारी को लेकर गंभीर सोच शुरू हो चुकी होगी। उनका मानना है कि 2026 तक यह लगभग तय हो जाएगा कि भविष्य में भाजपा का चेहरा कौन होगा। हालांकि यह नाम कौन सा होगा, इसका खुलासा अभी ज्योतिष भी साफ तौर पर नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना जरूर है कि रास्ता इसी दौरान तय हो सकता है।

ज्योतिषी पवन सिन्हा ने कहा,

"इस दौरान मोदी जी के मन अपने उत्तराधिकारी तय करने की बात जरूर चल रही होगी। फरवरी 2025 से, जब मंगल में शनि आया तो उनके मन में उत्तराधिकारी तय करने की बात जरूर उठेगी। तो ये तो तय है कि उनका उत्तराधिकारी इस साल जरूर तय हो जाएगा।

22 जनवरी से हर परिवार को ₹10 लाख तक फ्री इलाज, जानें पूरी डिटेल

(जीएनएस)।

पंजाब सरकार राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी हेल्थ स्कीम मानी जा रही है। इसके तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज राज्य के निवासियों को मिलेगा। यह कमजोर आर्थिक तबकों से आने वाले लागों के लिए एक बड़ी राहत बनकर साबित हो सकती है। सीएम भगवंत मान ने इसे स्वास्थ्य के लिहाज से क्रांतिकारी योजना बताया है।

क्या है मुख्यमंत्री सेहत योजना

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी खर्च से राहत देना है। योजना के अंतर्गत सरकारी के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मरीज को इलाज के समय किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा, पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कठव इलाज, दुर्घटना में इलाज सहित सैकड़ों गंभीर और महंगे इलाज शामिल किए जाएंगे। सामान्य बीमारियों से लेकर जटिल सर्जरी तक इस योजना में कवर किए जाने की संभावना है। किन लोगों को मिलेगा लाभ

- इस योजना का लाभ पंजाब के सभी स्थायी निवासियों को मिलेगा।
- राज्य के सभी परिवार, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हों या ऊपर उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- पहले से चल रही स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि यह योजना "यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज" के सिद्धांत पर आधारित होगी। आय की सीमा इसमें बाधा नहीं बनेगी।

योजना के लाभ के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें शामिल हैं:

आधार कार्ड

पंजाब का निवास प्रमाण पत्र

परिवार पहचान पत्र / राशन कार्ड

मोबाइल नंबर

आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा गया), कैसे मिलेगा कार्ड और पंजीकरण

सरकार योजना के लिए अलग से पोर्टल और हेल्थ कार्ड जारी कर सकती है। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव होगा। अस्पताल में इलाज के दौरान इसी कार्ड के जरिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और किसी भी परिवार को इलाज के अभाव में कर्ज या संपत्ति बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

बाइक सवार बदमाशों का तांडव, झांसी बायपास पर युवक की गोली मारकर हत्या

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के झांसी बायपास पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को सिर में गोली मार दी।

गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

मृतक की पहचानः गांव लौटते समय हुआ हमला

मृतक की पहचान रामपाल पुत्र लाखन सिंह गुर्जर (36) निवासी गांव जैदपुरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामपाल अपने दो साथियों खुश गुर्जर और भगवान सिंह गुर्जर के साथ बुंदेला कॉलोनी से अपने गांव जैदपुरा लौट रहा था।

तीनों एक ही बाइक पर सवार थे-

बाइक खुश गुर्जर चला रहा था

बीच में भगवान सिंह बैठे थे

पीछे रामपाल बैठा हुआ था

पीछे से आए बदमाश, कट्टे से किया फायर

जैसे ही उनकी बाइक झांसी बायपास पर पहुंची, पीछे से एक अन्य

बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश आए। बदमाशों ने बिना कोई चेतावनी दिए कट्टे से फायर कर दिया। गोली सीधे रामपाल के सिर के पीछे हिस्से में लगी, जिससे वह बाइक से गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी तेजी से मौके से फरार हो गए।

मौके पर पहुंची पुलिस, शव पोस्टमार्टम को भेजा

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मौके से खाली कारतूस और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

साथी का बयानः हालिया कोई रंजिश नहीं

मृतक के साथ मौजूद खुश गुर्जर ने पुलिस को बताया कि- "रामपाल की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। हाल ही में कोई विवाद भी नहीं हुआ था। हालांकि दीपावली के समय गांव में परिहार समाज के कुछ लोगों से विवाद जरूर हुआ था।" पुलिस इसी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

पुलिस का बयानः नामजद आरोपी, तलाश जारी

दतिया की एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि- "मामले में अंशुल परिहार, केपी परिहार, मलखान परिहार सहित तीन अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

इलाके में दहशत, बढ़ी पुलिस गश्त

दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद झांसी बायपास और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।

दिनदहाड़े हत्या ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

दतिया में सरेआम हुई इस हत्या ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाइक सवार बदमाशों द्वारा खुलेआम फायरिंग कर हत्या कर देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब सबकी नजरें पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं।

मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए तैयारी पूरी, 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन का प्रशासन का अनुमान

श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 12100 फीट लम्बाई में घाटों का निर्माण, कम से कम पैदल चलने के लिए घाटों के नजदीक बनाई गई पार्किंग

42 पार्किंग स्थल का निर्माण, आवागमन सुगम बनाने के लिए गोल्फ कार्ट और रैपिडो बाइक सेवा होगी मददगार

स्वच्छता के लिए 3300 स्वच्छता कर्मी तैनात, मेला क्षेत्र में 25,880 टॉयलेट का निर्माण

यातायात एवं भीड़ प्रबन्धन हेतु एआई सर्विलांस बेस्ड अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्राज्यीय कार्ययोजना का विकास

प्रयागराज, 13 जनवरी। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्राति 15 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान संपन्न कराने के बाद अब मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए कमर कस ली है। इसके लिए स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का प्रशासन का अनुमान है।

प्रशासन ने तैयार किया भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान

माघ मेला-2024 में इस पर्व पर 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार लगभग तीन गुना अधिक श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान तैयार किया है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है भीड़ प्रबन्धन एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत इस बार 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गयी है, जिसमें लगभग एक लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। माघ मेला 2025-26 में कुल 12100 फीट लम्बाई में घाटों का निर्माण किया गया है जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं चेंजिंग रूम, पुआॅल, कॉसा, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। मेला अधिकारी के अनुसार माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में दोनों नदियों में गिरने वाले सभी 81 नालों की टैपिंग की जा चुकी है। निरंतर गंगा जल की मॉनिटरिंग हो रही है।

स्वच्छता , सुरक्षा और सुगम परिवहन को प्राथमिकता

शासन के निर्देश पर माघ मेले में स्वच्छता , सुरक्षा और सुगम परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है। मेला अधिकारी ऋषिराज बताते हैं कि माघ मेले को खुले में शौच मुक्त (ड.ऊऋ), दुर्गन्ध मुक्त और गंगा में जीरो डिस्चार्ज हेतु लगभग 25,880 शौचालय, 11 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 25 सक्शन गाड़ियां एवं 3,300 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं। श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुलभ आवागमन हेतु बाइक टैक्सी और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गयी है। माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज पांडेय बताते हैं कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में 17 थाने व 42 पुलिस चौकी, 20 अग्निशमन स्टेशन, 07 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन वॉच टावर, 01 जल पुलिस थाना, 01 जल पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा 04 जल पुलिस सब कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। 8 किलोमीटर से अधिक डीप वाटर बैरीकेडिंग एवं 02 किलोमीटर रिवर लाइन (एकल दिशा मार्ग हेतु) लगायी गयी है।

मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है। नगर एवं मेला क्षेत्र में पूर्व से स्थापित सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त एआई युक्त कैमरों सहित 400 से अधिक कैमरों के माध्यम से क्राउड मानिटरिंग, क्राउड डेन्सिटी एनालिसिस, इन्सीडेन्ट रिपोर्टिंग, स्वच्छता एवं सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था की गयी है।

मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण की बढी जागरुकता

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु महिला थाना, थाना कोतवाली सुनगढी, थाना कोतवाली सदर,थाना गजरौला,थाना न्यूरिया,थाना अमरिया,थाना जहानाबाद,थाना करेली,थाना माधव टांडा,थाना दियूरिया कला,थाना बिलसंडा,थाना बीसलपुर कोतवाली, थाना पूरनपुर कोतवाली,थाना हजारा, थाना सेहरामऊ उत्तरी की

महिला सुरक्षा केंद्र टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर छात्राओं को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुये, महिला सम्बन्धी कानूनों, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महिला सशक्तिकरण, साइबर थाना पुलिस टीम के द्वारा गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले, किशोरियों बालिकाओं बालिकाओं महिलाओं को यौन अपराधों, साइबर अपराधों और

मोबाइल फोन पर अनैतिक तरीके से लोगों को फ्रॉड सूचनाओं के द्वारा अपने चंगुल में फंसा कर उनका दुरुपयोग करने और

शोषण करने की क्रियाकलापों से बचाने के लिए पुलिस की टीमों के द्वारा लगातार जागरूक करने

का अभियान तेज किया हुआ है।

स्कूल कॉलेज और गांव के मार्गो पर अनैतिक सामाजिक लोगों के द्वारा अगर महिलाओं किशोरियों छात्राओं को इस तरह से परेशान किया जाता है, या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही हो। इसकी सूचना सार्वजनिक करने में या पुलिस को देने में महिलाओं छात्र-छात्राओं को संकोच होता है। इससे बचने और उन्हें जागरूक होने के लिए पुलिस द्वारा कॉलेज के गेट पर शिकायती बक्से लगाए गए हैं।

जिन्हें पुलिस थाना के द्वारा कालेजों में ताले से बंद किया गया है। पुलिस की टीमों के द्वारा पूर्ण शिकायती बक्सों को चेक करके संबंधित पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास तेज किया जा रहे हैं। इस अभियान से छात्र-छात्राओं, महिलाओं की सुरक्षा में साइबर अपराधों, यौन अपराधों, और सामाजिक तत्वों से बचने के लिए जागरूकता बढ़ने लगी है। इसके संकेत थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क के द्वारा भी अच्छे संकेत बताए गए हैं।

अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

पीलीभीत (जीएनएस)।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु तीन दिवसीय सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन एवं समापन आदरणीय उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य श्री दरवेश कुमार द्वारा किया गया। समापन अवसर पर प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सामाजिक विज्ञान विषय प्रशिक्षण प्रभारी डायट प्रवक्ता विजय कुमार ने कक्षा 9 व 10 हेतु तैयार प्रतिदीप्त एवं बोध मॉड्यूल के माध्यम से गतिविधि आधारित, विश्लेषणात्मक एवं छात्र-केंद्रित शिक्षण पर प्रकाश डाला। विषय सन्दर्भदाता वीरेंद्र कुमार, बलवंत

कुमार, रोहित कुमार, शिवेंद्र कुमार, पुष्पराज, अजय कुमार एवं विजय सिंह ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया।

अंग्रेजी विषय प्रशिक्षण का संचालन प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. सुनीता विष्ट के निर्देशन में किया गया। विषय सन्दर्भदाता रवि कुमार वर्मा, सुधीर कुमार एवं प्रमोद कुमार द्वारा माध्यमिक कक्षाओं हेतु पठन साहित्य, व्याकरण, प्रश्न निर्धारण, कविता पाठ योजना, भाषा कौशल विकास, शब्दावली निर्माण तथा पाठ योजना/प्रदर्शन योजना पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के सफल आयोजन में डायट के स्वदेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, अमित कुमार, अमित शर्मा, नीलेशनाथ, मंजुलता, स्मिता लोधी, सुनीता विष्ट, मेघा अग्रवाल एवं पुलकित शर्मा तथा तकनीकी सदस्यों रविन्द्र कुमार एवं निर्मित कुमार का विशेष योगदान रहा।

गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे को फिर से वाया पीलीभीतः केंद्र सरकार की मंजूरी

गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की मेहनत रंग लाई, नितिन गडकरी ने जारी की अधिसूचना

(जीएनएस)।

पीलीभीत। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे को पुनः पीलीभीत के रास्ते ले जाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की सतत पैरवी के फलस्वरूप केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। इस खबर पर राज्यमंत्री के जन सहयोग कार्यालय पर कार्यकताओं ने खुशी जताते हुए एक-दूसरे को मिठाई

बांटी और केंद्र मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

पहले इस एक्सप्रेसवे को बरेली-पीलीभीत मार्ग से बनाने की मंजूरी थी, लेकिन बाद में इसे बरेली-शाहजहांपुर-लखीमपुर होते हुए गोरखपुर तक ले जाने का संशोधन कर दिया गया था, जिसमें पीलीभीत को दरकिनार किया गया। इस पर राज्यमंत्री संजय गंगवार ने 25 अगस्त 2025 को मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा और दिल्ली में व्यक्तिगत भेंट कर पीलीभीत मार्ग बहाल करने का अनुरोध किया। अब एक्सप्रेसवे बरेली-नवाबगंज से होकर बीसलपुर तहसील के 39 गांवों और सदर तहसील के आधा दर्जन गांवों से गुजरेगा।

राज्यमंत्री ने पत्र में पीलीभीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह नेपाल सीमा से सटा तराई क्षेत्र है, जहां चीनी उद्योग, गेहूं उत्पादन और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से पर्यटन फल-फूल रहा है। यहां एशिया की सबसे बड़ी खमीर फैक्ट्री (ईस्ट) की स्थापना हो रही है और अन्य औद्योगिक इकाइयों के प्लांट लगने की प्रक्रिया चल रही है। एक्सप्रेसवे से व्यापारिक आवागमन आसान होगा, रोजगार बढ़ेगा और जनपद का तीव्र विकास होगा।

इस मंजूरी पर राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री नितिन गडकरी के प्रति हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि नई सौगात से पीलीभीतवासियों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे।

संजय सिंह गंगवार

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अवध प्रांत से चलकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को जाने वाली 32सौ किलो मीटर की स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत

(जीएनएस)।

बाराबंकी ।

अवध प्रांत से चलकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को जाने वाली 32सौ किलो मीटर की स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत पीडब्लूडी गेस्ट हाउस बाराबंकी के सामने किया गया साथ ही स्वदेशी उद्घोष और नारे लगाकर नागरिकों को जागरूक किया गया ।

यात्रा क्षेत्रीय संयोजक अनुपम श्रीवास्तव के नेतृत्व में करीब 40 जिलों में जाएगी । इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तुएं अधिकाधिक प्रयोग की जाए और विदेशी वस्तुओं का त्याग कर देश की अर्थव्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो ।

विश्वजीत शर्मा संघर्ष वाहिनी प्रमुख अवध प्रांत व नरेंद्र पांडे सह संयोजक जनपद बाराबंकी ने रथ यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर अधिवक्ता मनोज राजपूत पूर्व कार्यकारिणी सदस्य जिला बार एसोसिएशन, महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री व कोषध्यक्ष जिला बार एसोशिएशन,अनुराग शुक्ला वर्तमान कोषाध्यक्ष, अशोक द्विवेदी पूर्व मंत्री प्रशासन जिला बार, रामनारायण मिश्र वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल वर्मा वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य जिला बार एसोसिएशन, नवनीत वर्मा, प्रमोद कनौजिया, हिमांशु शर्मा, राजेश यादव, अनिल मिश्रा, मायाराम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पर समाजसेवी उपस्थित रहें।

रेलवे प्लेटफॉर्म पर बुलेट दौड़ाईः केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया, पुलिस वीडियो से पहचान में जुटी

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए कुछ युवकों ने बुलेट बाइक दौड़ाई और प्लेटफॉर्म पर ही केक काटकर जन्मदिन मना लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है,

जिससे रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं।वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक अपनी बुलेट बाइक को प्लेटफॉर्म के मुख्य हिस्से तक ले आए और वहां तेज रफ्तार से दौड़ाई।

रेलवे नियमों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है।

इसके बावजूद युवकों ने न सिर्फ बाइक दौड़ाई, बल्कि केक काटकर जमकर हंगामा भी किया।

इस दौरान कई यात्री डर गए।स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

शिकायतें की गईं, लेकिन फ्छऋ या स्टेशन प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती। इससे युवकों का हौसला बढ़ा और उन्होंने सार्वजनिक जगह को निजी पार्टी स्पॉट बना लिया। वीडियो वायरल होते ही पूरनपुर थाना अध्यक्ष पवन पांडे ने संज्ञान लिया। उन्होंने बताया,

"वीडियो के आधार पर आरोपी युवकों की पहचान तेजी से की जा रही है। सुसंगत धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

" रेलवे सुरक्षा बल को भी निर्देश दिए गए हैं।इस घटना ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों पर शिकंजा कसा जाएगा।

पीलीभीत के सभी ग्राम पंचायतों में लुप्त हो रहे कुएंः ग्रामीणों को पानी की किल्लत, शादी की रस्में प्रभावित

(जीएनएस)। पीलीभीत,13 जनवरी 2026ः जिले की ग्राम पंचायतों में पारंपरिक कुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भूजल स्तर में कमी, रखरखाव की कमी और आधुनिक नलकूपों पर निर्भरता के कारण ये कुएं तेजी से लुप्त हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

▪ समस्या की गहराई

पीलीभीत जिले की लगभग 709 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश में पुराने कुएं सूख चुके हैं या मलबे से भरे पड़े हैं। बरखेड़ा, पूरनपुर, मरौरी और गंज ब्लॉकों के गांवों में ग्रामीणों ने बताया कि गर्मियों में तो पानी का संकट चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन अब सर्दी में भी नल सूख रहे हैं। जिले में नेर और घाघरा नदियों के किनारे होने के बावजूद भूजल का दोहन बेतहाशा हो रहा है, जिससे कुओं का जलस्तर लगातार गिर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायतें कुओं के जीर्णोद्धार के लिए बजट आवंटित होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।

▪ ग्रामीणों पर असर

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चे दूर-दराज के हैंडपंप या नलकूपों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे

रोजमर्रा का समय पानी ढोने में ही निकल जाता है। खासकर शादी-विवाह के अवसर पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। पारंपरिक रस्मों जैसे 'मंडप बांधना', 'कलश यात्रा' या 'भात भरना' में स्वच्छ कुएं का पानी अनिवार्य होता है, लेकिन अब टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। बरखेड़ा ब्लॉक के दौलतपुर पट्टी गांव की रहने वाली सुनीता ने बताया, "हमारी शादी में कुएं का पानी न होने से रस्में अधूरी रह गईं। महंगे टैंकर ने जेब ढीली कर दी।" इसी तरह, जबानाबाद क्षेत्र के हरचुईया गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक शादी कार्यक्रम में पानी की कमी के कारण कई रस्में टालनी पड़ीं।

▪ प्रशासन की लापरवाही

जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। लाखों रुपये के बजट से बने कचरा निस्तारण केंद्रों की तरह कुओं का रखरखाव भी कागजों तक सीमित है। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 'जल जीवन मिशन' के तहत नलकूप योजना चल रही है, लेकिन पारंपरिक कुओं को पुनर्जनन की कोई योजना नहीं है। स्थानीय विधायक और ब्लॉक प्रमुखों के बीच भी इस मुद्दे पर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखा। पर्यावरणविदों का कहना है कि वर्षा जल संचयन और कुओं के पुनः निर्माण से समस्या हल हो सकती है।

▪ ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल कुओं के सर्वेक्षण, सफाई और पुनर्भरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि शासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिले में मिशनशक्ति जैसी सामाजिक योजनाओं के साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पानी निकासी पास जगह इंटरलॉकिंग धंसने लगी

बाराबंकी । जिले की निकासी पास की जगह पर सड़क देखें तो एक साइड स्तर पर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड विकास भवन के अंतगर्त गोकुलनगर में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई , ऐसीी चचाओं से जानकारी प्राप्त हो रहीं है । कि डूडा के अंतगर्त बन रही सड़क में ठेकेदार ने नियमों का पालन नहीं किया। ठेकेदार ने नीचे कच्ची गिट्टी का कोट नहीं डाला। उसने सीधे डस्ट पर इंटरलॉकिंग ईंटें बिछा दीं। हल्के वाहनों के निकलने से पानी

इंटरलॉकिंग धंसने लगी है। अगर उस रास्तें अंदर ही अंदर धसनें लग रहा हैं। अभी इंटरलॉकिंग के बीतें दो पखवारें भी नहीं हुए कि गुणवक्ता प्रभावित हो रही , वाहनों के आवागमन में असुविधा हो रहीं जबकि स्थानीय लोग शासन व प्रशासन से मांग किया हैं कि पुनः मरम्मत कार्य सम्पन्न किया जाय , लोगों को वाहनों के द्वारा आवागमन असुविधा नहीं होगी ।

गो सेवा से लखपति बन गईं झांसी की प्रवेश कुमारी

सौर ऊर्जा से हाई क्वॉलिटी चारा बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं

नए स्टार्टअप से गांवों में शुरू हुई सामूहिक भागीदारी की प्रथा

सीएम योगी के आत्मनिर्भर विजन को मिल रही रफ्तार

लखनऊ, 13 जनवरी : बुंदेलखंड की धरती अब न केवल शौर्य के लिए, बल्कि महिला उद्यमिता के रूप में भी पहचानी जा रही है। झांसी की प्रवेश कुमारी ने चारा बनाने की यूनिट के जरिये वह मुकाम हासिल किया है, जो आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के सपने को धरातल पर उतारते हुए प्रवेश ने सौर ऊर्जा की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले पशु चारे की यूनिट स्थापित कर न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है।

बिजली खर्चा शून्य, मिल रहा सस्ता और पोषक चारा

इस उद्यम की सबसे बड़ी विशेषता इसका ईको-फ्रेंडली होना है। योगी सरकार और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (ऊअ) के सहयोग से स्थापित यह यूनिट पूरी तरह 18 ‘ह सौर ऊर्जा प्रणाली पर संचालित होती है। इससे बिजली का खर्च शून्य के बराबर है, जिससे चारे की उत्पादन लागत कम आती है। सस्ता और पोषक चारा मिलने से स्थानीय डेयरी किसानों के पशुओं का स्वास्थ्य सुधरा है और दूध उत्पादन क्षमता में भी इजाफा हुआ है।

रोजगार और सामूहिक भागीदारी की नई प्रथा

प्रवेश कुमारी आज करीब 25,000 रुपये प्रति माह कमा रही हैं। उनके इस स्टार्टअप ने गांव की सामाजिक संरचना को भी बदला है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है। गांव की अन्य महिलाओं को स्थायी आय और आर्थिक स्वतंत्रता मिली रही है। जिससे वे भी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

खरीद से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण तक की जिम्मेदारी खुद संभालती हैं

यहां आधुनिक मशीनरी और मानकीकृत तकनीकों से पौष्टिक चारा तैयार किया जाता है। साथ ही स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। प्रवेश केवल उद्यमी नहीं, बल्कि एक कुशल मैनेजर भी हैं। वे कच्चे माल की खरीद से लेकर वित्तीय खातों, उत्पादन योजना और गुणवत्ता नियंत्रण तक की जिम्मेदारी खुद संभालती हैं। उनकी इस सक्रिय शैली और वित्तीय अनुशासन के कारण उनके 'गोमाता कैटल फीड' को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है।

छोटे प्रयास से बड़ी शुरूआत

शुरूआत एक छोटे प्रयास से हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के मार्गदर्शन ने इसे व्यवसाय बना दिया। आज गांव की महिलाएं साथ मिलकर काम कर रही हैं।

– प्रवेश कुमारी, महिला उद्यमी

योगी सरकार की पहल से रफ्तार पकड़ रही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 94 नई इकाइयां स्थापित

₹648.63 लाख का पूंजी निवेश, 2,586 युवाओं को मिला रोजगार

10 लाख रुपये तक बैंक ऋण और ब्याज अनुदान से बढ़ा आत्मनिर्भरता का मार्ग

लखनऊ, 13 जनवरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण औद्योगिकीकरण सबसे ऊपर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक योजना के अंतर्गत 94 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसके तहत ₹648.63 लाख का पूंजी निवेश संभव हुआ है। इसके माध्यम से 2,586 युवाओं को रोजगार दिलाने में सफलता मिली है। यह आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष में योजना ने मजबूत प्रगति दर्ज की है और शेष अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

योग्य बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण

इस योजना ने गांवों में उद्योग स्थापित कराकर स्थानीय युवाओं को उनके ही घर के पास रोजगार उपलब्ध कराने का रास्ता खोला है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित एवं तकनीकी योग्य बेरोजगार युवक-युवतियों को 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योगी सरकार ने उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी की बड़ी सुविधा दी है, जिसमें सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए 4% से ऊपर का ब्याज सरकार देती है, जबकि आरक्षित वर्ग के उद्यमियों का पूरा ब्याज सरकार वहन करती है।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से चयन

योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला उद्यमी पात्र हैं। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से की जाती है। सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जबकि आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होता है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में और अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़कर स्व-रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

योगी सरकार का ग्रामीण विकास मॉडल

योगी सरकार ग्रामीण विकास को केवल सड़क और बिजली तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि ग्रामीण उद्योगों का नेटवर्क विकसित कर रही है। पारंपरिक कारीगरों व हस्तशिल्पकारों को सशक्त बना रही है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही, स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार सृजन हो रहा है। सरकार का मानना है कि ह्लगांव मजबूत होंगे तो प्रदेश मजबूत होगा।ह्व इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया जा रहा है।

पीलीभीत टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल: ठलअकने एजेंसी पर ठोका 3.30 लाख का जुमार्ना, 3 कर्मचारी निष्कासित

(जीएनएस)।

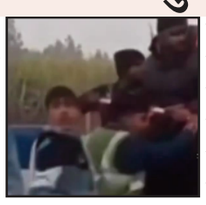

पीलीभीत/बीसलपुर हाईवे (ठल-731) पर स्थित टिकरी टोल प्लाजा पर कार्यरत एजेंसी पर एनएचएआई ने 3.30 लाख रुपये का भारी जुमार्ना लगाया है। साथ ही एजेंसी ने वायरल वीडियो में शामिल तीन कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। एनएचएआई के सख्त रुख से टोल प्लाजा पर खलबली मच गई है।बीते 29 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टोल कर्मियों द्वारा वाहन सवारों से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा। वीडियो में टोल पर वाहनों की लंबी कतारें रुकी दिखीं। पीलीभीत से बीसलपुर हाईवे के टिकरी टोल पर गुंडागर्दी की इस घटना पर बरेली एनएचएआई ने संज्ञान लेते हुए जांच कराई।हालांकि कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन एनएचएआई ने लापरवाही बरतने पर एक्शन ले लिया। एजेंसी पर 3.30 लाख का जुमार्ना लगाया गया और भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी।टोल प्लाजा के मैनेजर प्रवीन सिंह ने बताया कि तीन दोषी कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सभी कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अनुशासन के साथ काम करें, ताकि भविष्य में कोई वाद-विवाद या मारपीट की घटना न हो। एनएचएआई की इस कार्रवाई को टोल संचालन में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

करछना तहसील में सीज जमीन पर खुलेआम खेती, आईजीआरएस शिकायत के बाद भी कार्रवाई शून्य

(जीएनएस)।

लखनऊ/प्रयागराज

लेखपाल,तहसीलदार, एस डी एम, डी एम की संरक्षण में हो रहा है।

करछना तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। तहसील प्रशासन द्वारा सीज की गई भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है, जबकि इस संबंध में क्क्ष्ग्र पोर्टल पर शिकायत 40017522134121 को सन 2020 40017520081777 को सन 2022, 40017525080895 को सन 2025 भी दर्ज कराया जा चुका है, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि को प्रशासन द्वारा पूर्व में सीज किया गया था, लेकिन स्थानीय दबंगों द्वारा फसल बोकर खेती की जा रही है। इससे न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

शिकायतकर्ता महेश सिंह पुत्र राजबहादुर ग्राम बबुरा परगना अरेल करछना प्रयागराज का आरोप है कि क्क्ष्ग्र पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर निरीक्षण तक नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, या फिर मिलीभगत के चलते कार्रवाई टाली जा रही है।

स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि सीज जमीन पर खुलेआम खेती होती रही और प्रशासन मौन रहा, तो आम जनता का कानून से भरोसा उठ जाएगा।

अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेकर सीज भूमि को कब्जा मुक्त कराता है और दोषियों पर कार्रवाई होती है।

करछना तहसील मे सरकारी जमीन सरकारी राजस्व कर्मचारी के साथ मिलके कब्जा किया गया हैरिपोर्ट मे लिखा गया कि खाली करा दिया है खाली है पूछता हु कहा पे खाली है जो कब्जे डर सरकारी जमीन पे आज भी काबिज हैक्यू तहसील के कर्मचारी बचा रहे है कब्जेदार को या मोटा रकम या भू माफिया है जो सरकारी जमीन कब्जा किया है

क्यू तहसील के कर्मचारी बचा रहे है कब्जेदार को या मोटा रकम या भू माफिया है जो सरकारी जमीन कब्जा किया है

इसमे डी एम ,एस डी एम ,तहसीलदार,नेखपाल के मिलि भगत

डीएम से गैंगस्टर के खिलाफ शिकायत: पीड़ित का आरोप डीएम के नाम दर्ज जमीन पर किया कब्जा,कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।

पीलीभीत,भू-माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक नया मामला सामने आया है। शहर के मोहल्ला बड़ा खुदागंज निवासी रिजवान खान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने एक पार्टी से जुड़े एक नेता और उसके गैंग पर करोड़ों की कीमती जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने अपनी पैतृक भूमि के सीमांकन और उसे कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में रिजवान खान ने बताया कि ग्राम पीलीभीत मुस्तकिल में उनकी विभिन्न गाटा संख्याओं (716, 731/2, 732, 733, 734 और 757/1) पर कुल लगभग 0.8740 हेक्टेयर भूमि स्थित है। आरोप है कि इस बेशकीमती भूमि पर सिविल लाइन नॉर्थ निवासी और समाजवादी पार्टी से जुड़े अहमद नबी पुत्र जमालुद्दीन ने अपने गैंग के साथ अवैध कब्जा कर रखा है।

शिकायतकर्ता का दावा है कि अहमद नबी एक पेशेवर भू-माफिया है और उस पर पूर्व में भी ऐसे कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। आरोप के अनुसार, दबंगों ने न केवल निजी भूमि पर कब्जा किया है, बल्कि जिलाधिकारी के नाम दर्ज सरकारी भूमि (गाटा संख्या 737/2) पर भी अवैध कब्जा कर उसका कुछ हिस्सा बेच दिया है। सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त की बात सामने आने से प्रशासन में चिंता बढ़ गई है।

पीड़ित रिजवान खान ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पहले भी की थी। जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। हालांकि, कुछ कारणों से अब तक प्रकरण का समाधान नहीं हो सका और न ही भूमि का सीमांकन हो पाया।

हाल ही में, पीड़ित ने पुनः प्रार्थना पत्र देते हुए जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि राजस्व टीम भेजकर भूमि का सीमांकन कराया जाए। उन्होंने भू-माफिया के चंगुल से अपनी निजी जमीन और सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। पीड़ित ने दबंगों से अपनी जान-माल का खतरा भी जताया है।

बिलसंडा थाना क्षेत्र के कनपरी गांव में दबंगई की हद पार बिना किसी अनुमति के पेड़ों पर चला आरा, पर्यावरण की खुलेआम हत्या

पीलीभीत (जीएनएस)।

पीलीभीत जनपद के बिलसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनपरी में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव निवासी रामरतन व शिवचरण पुत्रगण रामदयाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दबंगई के बल पर बिना किसी विभागीय अनुमति के शीशम, नीम, जामुन, शहतूत एवं यूकेलिप्टस सहित कई कीमती और पर्यावरण के लिए उपयोगी वृक्षों को कटवा दिया।ग्रामीणों का कहना है कि इन दबंगों ने खुले आम आरा चलवाकर हरे-भरे पेड़ों को नहस-नहस कर दिया, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है बल्कि सरकारी नियमों और कानूनों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं इस अवैध वृक्ष कटान से आक्रोशित ग्रामीणों ने संबंधित वन विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे दबंग और अधिक मनमानी करने से बाज नहीं आएंगे।अब देखना यह होगा कि प्रशासन और वन विभाग इस गंभीर मामले में कितनी तत्परता दिखाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले दबंगों पर कब तक कार्रवाई होती है।

स्वदेशी अपनाकर ही भारत बनेगा विश्व गुरु: सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने निकाली स्वदेशी जागरूकता रैली

(जीएनएस)। प्रयागराज

सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा आज नगर में भव्य 'स्वदेशी जागरूकता रैली' का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) के उपलक्ष्य में निकाली गई इस रैली के माध्यम से युवाओं ने नागरिकों को विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया।

रैली का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेश चन्द्र तिवारी और मुख्य अतिथि विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक श्री अनिल बाबू जायसवाल एवं विद्वत परिषद प्रमुख श्री सतीश कुमार गुप्त जी ने हरी झंडी दिखाकर किया। भारत माता के जयघोष और "स्वदेशी अपनाओ-देश बचाओ" के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। विद्यालय के भैया बहिनों ने अपने हाथों में स्वदेशी को पुष्ट करने वाले स्लोगन लिखें हुए तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले प्रेरक वाक्य लिखे हुए थे।

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी का मार्ग अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में केवल भारत निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करने का संकल्प लें। रैली विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर भरद्वाज(अल्लापुर) के मुख्य बाजार, लेबर चौराहा, मटियारा रोड़, टैक्सी स्टैंड बाघम्बरी रोड़ मार्ग से होते हुए वापस विद्यालय पर संपन्न हुई। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं विद्वत प्रमुख ने अपनी शुभकामनायें देते हुए सभी भैया बहिनों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हुए स्वदेश, स्वराष्ट्र के उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करते रहने का आग्रह करते हुए अपनी शुभकामनायें दी` इस कार्यक्रम का नगर व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभीआचार्य बंधु भगिनी, सम्मानित प्रबंध समिति, सम्मानित नगर के नागरिक एवं बड़ी संख्या में भैया बहिनों की गरिमामय उपस्थिति रही।

पत्रकार हों गए 'बे-सहारा' अपने दौर में पत्रकारों को सबसे अच्छा वेतन देने वाला अखबार बंद

(जीएनएस)।

लखनऊ। कल हमने मीडिया हाउस छोड़ कर पत्रकारों के द्वारा यूट्यूब चैनल के जरिए पत्रकारिता करने में आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से बात की थी पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सीधा प्रमाण आज देखने को मिला जब राष्ट्रीय सहारा अखबार का मसला सामने आया. असल में पत्रकारिता के सामने आने वाली चुनौतियों को समझपाना उन लोगो के बस में नही है जिन्होंने पत्रकारिता की नौकरी नहीं की कई लोग पत्रकारिता में दलाली करने के लिए आते है उनके लिए चुनौतियों का कोई मतलब नही होता क्योंकि उनका काम वेतन से नहीं चलता उनको केवल दलाली से मतलब होता है ऐसे लोग रंगे सियार होते है यह पोस्ट ऐसे लोगो के लिए नहीं है यह बात उनकी समझ में आएगी जिनका घर परिवार पत्रकारिता से चलता है जब राष्ट्रीय सहारा अखबार शुरू हुआ था वो लखनऊ के सबसे अच्छी सैलरी वाला अखबार था उनका ऑफिस सबसे अच्छा था राष्ट्रीय सहारा वर्ष 1992 से लगातार प्रकाशित हो रहा था, लेकिन 8 जनवरी 2026 को बिना किसी पूर्व नोटिस के इसका प्रकाशन अचानक रोक दिया गया। जिससे सैकड़ों पत्रकार और कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कोरोना के बाद बहुत सारे पत्रकारो के सामने नौकरी जाने, वेतन कटौती, और तमाम सुविधों में कटौती की गई. ऐसे में पत्रकारों की मदद करने कोई नही आया. सहारा अखबार के जो पत्रकार साथी बेरोजगार हुए हैं उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है इनमें तमाम पत्रकार ऐसे हैं जिनको अब जॉब नहीं मिलेगी इस तरह की चुनौतियों को असली पत्रकार ही समझ सकते हैं, दलाल नहीं।

किसान आत्महत्या केस, सुखवंत सिंह के भाई से सीएम धामी ने की फोन पर बात

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के किसान स्व. सुखवंत सिंह की मृत्यु के मामले में परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि इस मामले की जांच में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ है और इस दुखद घटना के लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को स्व. सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह से दूरभाष पर वार्ता कर हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत सुखवंत सिंह के पिता एवं अन्य परिजनों की मौजूदगी में उनके भाई के साथ दूरभाष पर वार्ता कर कहा कि इस दुखद घटना की भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन सरकार इस मामले में दोषी लोगों को कानूनी रूप से सख्त से सख्त सजा दिलवाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल उच्चाधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही कुमांऊॅ कमिश्नर को मजिस्टीरियल जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर कीमत पर परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी घटना होने पर सरकार ने तत्परता एवं प्रतिबद्धता से कार्रवाई सुनिश्चित पीड़ितों के न्याय दिलाने का काम किया है। मुख्यसमंत्री ने कहा कि वह जल्दी पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे।

ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी किसान के हल्द्वानी में आत्महत्या करने के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर से लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच सौंपी गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के सभी तथ्यों व परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके।

ऊधमसिंह नगर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी सुखवंत सिंह (40) ने गौलापार स्थित होटल में शनिवार रात करीब ढाई बजे अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उस समय होटल में मृतक की पत्नी और बेटा भी मौजूद था। जिसमें अभी तक प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है।